(b) whether some industrial units, vehicles and indiscriminate and illegal denudation of forests are the main causes of pollution;

(c) if So, whether Government pre-pose to formulate any comprehensive policy for conservation of environment and for checking the pollution.

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THS MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTs (SHRI KAMAL NATH): (a) According to the report "Global Pollution and Health" prepared by World Health Organisation (W.H.O) and United Nations Environment Programme (UNEP), the levels of suspended particulate matter (SPM) in respect of Delhi Calcutta and Bom bay rank 4th, 6th and 13th respectively among 54 cities of the World. With respect to sulphur dioxide, these cities rank 27th, 18th and 37th respectively, among 41 cities.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) The Government of India have formulated comprehensive policies for conservation of enciron-ment and checking pollution. These include Policy Statement for Abate ment of Pollution and the National Conservation Strategy and Policy Statement on Environment and Deve lopment. The Policy Statement for Abatement of Pollution envisages in tegration of environmental and eco nomic aspects of development plan ning lays stress on preventive aspects of pollution abatement and promo tion of technological inputs to redu ce industrial pollutants. The Na tional Conservation Strategy and Policy Statement on Environment and Development sets out priorities on conservation of natural resources such as land and water prevention and control of atmospheric pollution in cluding noise pollution and indus-trial development by using a mix of promotional and regulatory steps, (e) Does not arise.

वन-रहित क्षेत्रों में खनन-कार्य पर से पाबंदी हटाना

7936. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और अन्य राज्यों में पर्यावरण के नाम पर ऐसे क्षेत्रों में भी खनन-कार्य पर पाबंदी लगा दी गई है, जहां वन नहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार इन नियमों में परिवर्तन करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) (ख) और (घ) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे संरक्षण क्षेत्रों के अलावा खनन कार्य पर देश में कहीं भी प्रतिबंध नहीं है । इसकी अधिसूचनाओं के उपबन्धों के तहत आने वाले पारिस्थितिकीय रूप से नाजुक क्षेत्रों में विनियमित किया गया है । जिनमें दून घाटी, अरावली की पहाड़ियां तटीय विनियमन क्षेत्र, मुरूड-जंजीरा और दहानू शामिल हैं । इसके अलावा, परियोजना आयोजना में पर्यावरणीय सरोकारों को शामिल करने की दृष्टि से सरकार ने 4-5-94 को यथा-संशोधित दिनांक 27-1-94 की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना जारी की है, जो अन्य बातों के अलावा, विशिष्ट सीमा से ऊपर खनन परियोजनाओं पर भी लागू होती है । चूंकि इन नियमों को हाल ही में अधिसूचित किया गया है इसलिए इनमें कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।